



2026:AHC: 54773-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 383/2006

महेंद्र और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अंजलि राजपूत, अंजली राजपूत, डी.आर. चौधरी,
डी.आर. आजाद, जे.एच. खान, कुलदीप कुमार,
एम. इस्लाम, पी.के. राजपूत, सचिन कनौजिया,
संजय कुमार यादव, संजय श्रीवास्तव, सौरभ गौर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

और 1 संबंधित वाद

22.01.2026 को निर्णय सुरक्षित

18.03.2026 को निर्णय पारित

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन कनौजिया, जो आपराधिक अपील संख्या 383 वर्ष 2006 में अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से अपील पर बहस करने के लिए नियुक्त न्याय मित्र के रूप में भी उपस्थित हुए और संबद्ध आपराधिक अपील संख्या 724 वर्ष 2006 में भी, साथ ही राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पवन कुमार श्रीवास्तव को सुना तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आपराधिक अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, बुलंदशहर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1059 वर्ष 1995 (राज्य बनाम महेन्द्र और अन्य), अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता, थाना स्याना, जिला बुलंदशहर में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.01.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 5,000/- रुपये के अर्थदंड और अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट होने वाली अभियोजन की कहानी का संक्षिप्त विवरण यह है कि 24.08.1995 को रात 22:45 बजे, थाना स्याना, जिला बुलंदशहर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्राम मकड़ी के एक श्री राकेश ने थानाध्यक्ष, थाना स्याना के समक्ष इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि लगभग ढाई माह पूर्व किसी बात को लेकर उसके पिता फतेह सिंह और उसके गांव के महेन्द्र के बीच कुछ हाथापाई हुई थी और महेन्द्र ने उसके पिता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और वह उसके पिता से दुश्मनी रखने लगा था। आज, वह और उसके दादा शिव चरण, चाचा चंद्र किरण और पिता फतेह सिंह राजनीतिक नेताओं का भाषण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुनकर अपने घर लौट रहे थे और जब शाम लगभग 5.00 बजे, वे अमर सिंह, जो अभियुक्त महेन्द्र का चाचा हैं, के घर के सामने तिराहे पर पहुंचे, तब अभियुक्त महेन्द्र और उसके गांव के बांके तथा नेमपाल और पप्पू पंडित, अमर सिंह की झोपड़ी से बाहर आए। वे तमंचों से लैस थे। सभी चारों अभियुक्तों ने उसके पिता फतेह सिंह को ललकारा और अभियुक्त महेन्द्र ने यह कहते हुए उकसाया कि फतेह सिंह को बचकर भागने नहीं देना चाहिए। इस पर, वह, उसके पिता, दादा और चाचा भागने लगे। चारों अभियुक्तों द्वारा उसके पिता का पीछा किया गया और उन्होंने देशी पिस्तौल से उन पर गोलियां चला दीं। फतेह सिंह की हत्या करने के बाद सभी अभियुक्त नहर की ओर भाग गए। इस घटना में कंछिद और उसका बेटा रतन सिंह भी शामिल हो सकते हैं। शोर मचाया गया लेकिन अभियुक्तों के डर से किसी ने वहां आने की हिम्मत नहीं की। डर के कारण अभियुक्तों का पीछा भी नहीं किया जा सका। वाहन उपलब्ध न होने के कारण उसके पिता का शव फूल सिंह के खेत में पड़ा था। डर के कारण सूचनादाता छिपकर पुलिस स्टेशन आया है।

4. इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र, बांके, नेमपाल और पप्पू के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 161/95 दर्ज की गई और इसका सार 24.08.1995 को रात 22:45 बजे जीडी संख्या 40 में दर्ज किया गया। विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष स्याना श्री वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उन्होंने सूचनादाता राकेश का बयान दर्ज किया, और उसके पश्चात उप-निरीक्षक जगदीश सिंह तथा पुलिस कांस्टेबल किशन सिंह और अन्य के साथ घटना स्थल के लिए प्रस्थान किया। मृतक के शव का पंचायतनामा पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में उप-निरीक्षक जगदीश सिंह द्वारा किया गया। पंचायतनामा कार्यवाही के पश्चात, मृतक के सीलबंद शव को कांस्टेबल किशन सिंह और कांस्टेबल सुंदर पाल के माध्यम से आवश्यक कागजातों के साथ पोस्टमार्टम के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मूर्दाघर भेज दिया गया। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से खून से सनी और सादी मिट्टी एकत्र की और उसका फर्द तैयार किया। उसने मृतक और अभियुक्तों से संबंधित 4 जोड़ी चप्पलें भी एकत्र कीं। उन्हें सील कर दिया गया और उनका फर्द तैयार किया गया। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 25.08.95 को उसने अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद उसने 15.11.1995 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त महेंद्र, बांके और नेमपाल के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि अभियुक्त पप्पू पंडित उर्फ महिपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, इसलिए उसका नाम अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र में शामिल नहीं किया गया था।

5. अभियुक्तों महेंद्र, बांके और नेमपाल के विरुद्ध मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा 29.11.1995 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदनुसार, इसे 04.12.1995 को सत्र परीक्षण संख्या 105/1995 के रूप में दर्ज किया गया।

6. अभियुक्तों महेंद्र, बांके और नेमपाल पर 19.01.1996 को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

7. अभियुक्त पप्पू पंडित को तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र 16 बी प्रस्तुत किया गया था। यह प्रार्थना पत्र 21.03.1998 को स्वीकार किया गया और तदनुसार अभियुक्त पप्पू उर्फ महिपाल को 05.09.2000 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत तलब किया गया। उस पर भी धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराधों का आरोप लगाया गया। उसने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग किया।

8. विचारण के लंबन के दौरान अभियुक्त नेमपाल की मृत्यु हो गई और इसलिए, उसके विरुद्ध विचारण 10.09.2001 को उपशमित हो गया।

9. अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-1 राकेश, पी.डब्ल्यू.-2 चंद्र किरण, पी.डब्ल्यू.-3 कांस्टेबल सुंदर पाल सिंह, पी.डब्ल्यू.-4 वीरेंद्र सिंह, पी.डब्ल्यू.-5 पुलिस उपाधीक्षक और पी.डब्ल्यू.-6 कांस्टेबल हेतराम सिंह का परीक्षण किया है।

10. पी.डब्ल्यू.-1 राकेश ने तहरीर रिपोर्ट को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है। पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. एम.के. बंसल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है। श्री वीरेंद्र सिंह ने पंचायतनामा रिपोर्ट को प्रदर्श क-3, पुलिस फॉर्म संख्या 13 को प्रदर्श क-4, फोटो लाश को प्रदर्श क-5, आरआई को लिखे पत्र को प्रदर्श क-6, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखे पत्र को प्रदर्श क-7, खून से सनी और सादी मिट्टी को कब्जे में लेने के संबंध में फर्द को प्रदर्श क-8, मृतक और अभियुक्त की 4 जोड़ी चप्पलों को कब्जे में लेने के संबंध में फर्द को प्रदर्श क-9, नक्शा-नजरी को प्रदर्श क-10, आरोप-पत्र को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया है। पी.डब्ल्यू.-6 कांस्टेबल हेतराम सिंह ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-12, मूल जीडी को नष्ट करने के संबंध में रिपोर्ट को प्रदर्श क-13, दिनांक 24.08.95 की जीडी संख्या 40 की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-14 के रूप में साबित किया है। पी.डब्ल्यू.-5 ने मृतक और अभियुक्तों की 4 जोड़ी चप्पलों को भौतिक प्रदर्श 1 से 4 के रूप में भी साबित किया है।

11. अभियोजन साक्ष्य के सामापन के पश्चात, अभियुक्तों महेंद्र, बांके और पप्पू पंडित तथा महिपाल का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया। अभियुक्त महेंद्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य झूठा है और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। अभियुक्त बांके ने भी कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य झूठा है और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और झूठा आरोप-पत्र दिया गया है। अभियुक्त पप्पू पंडित उर्फ महिपाल ने भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया साक्ष्य झूठा है और झूठी रिपोर्ट दी गई थी तथा झूठा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. अभियुक्तों द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:-

(i) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब हुआ है और अभियोजन पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब को स्पष्ट करने में विफल रहा है।

(ii) कि पी.डब्ल्यू.-1 राकेश मृतक फतेह सिंह का पुत्र है और पी.डब्ल्यू.-2 चंद्र किरण मृतक का भाई है और वे अत्यधिक हितबद्ध गवाह हैं तथा किसी अन्य स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है।

(iii) कि पी.डब्ल्यू.-1 राकेश ने अपने बयान में कहा है कि राजनीतिक नेता धर्मवीर का भाषण रात 8:05 बजे समाप्त हुआ और घटना स्थल पर पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटे लगे, और इस प्रकार उसके साक्ष्य से, यह साबित होता है कि घटना रात 8:05 बजे नहीं हुई जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है।

(iv) कि चोट संख्या 1 लगने के पश्चात, मृतक के लिए फूल सिंह के खेत तक भागना संभव नहीं था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय-पूर्व बनाई गई है क्योंकि पी.डब्ल्यू.-6 कांस्टेबल हेतराम सिंह ने अपनी प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 10-15 मिनट लगे, और उसके बाद जीडी में प्रविष्टि की गई जिसमें 5-10 मिनट लगे।

14. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दो चश्मदीद गवाह पेश किए गए थे और पी.डब्ल्यू.-1 तथा पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों में कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है, इसलिए, इस अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और यह खारिज होने योग्य है।

15. विरोधी दलीलों पर ध्यान देते हुए उनके संबंधित गुण-दोषों को तौलने के लिए, पहले गवाहों की गवाही पर ध्यान देना उपयुक्त होगा।

16. पी.डब्ल्यू.-1 राकेश मामले का सूचनादाता और मृतक का पुत्र है। उसने कहा कि लगभग 2 वर्ष और 2 महीने पहले शाम लगभग 5:00 बजे, वह, उसके पिता, चाचा और उसके दादा एक राजनीतिक नेता का भाषण सुनकर लौट रहे थे और जब वे लक्ष्मण नामक एक ग्रामवासी के घर के सामने पहुंचे, तब अभियुक्त महेंद्र, नेमपाल और पप्पू अपने हाथों में पिस्तौल लिए लक्ष्मण के घर से बाहर आए और वे उसके पिता की ओर दौड़े तथा उसके पिता फूल सिंह के खेत की दक्षिण दिशा की ओर भागे और तब अभियुक्तों ने उसके पिता पर गोली चला दी जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसने कहा कि पी.डब्ल्यू.-2 चंद्र किरण और उसके दादा शिव चरण ने इस घटना को देखा था। महेंद्र द्वारा एक लड़की को अपने घर में रात भर रुकने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



देने के बाद, महेंद्र और सूचनादाता के पिता के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके कारण, असहमति एक संघर्ष में बदल गई जिसके परिणामस्वरूप तब से चल रही दुश्मनी हो गई। झगड़े की घटना उसके पिता की मृत्यु से 2, ढाई महीने पहले हुई थी। उसने इस घटना की तहरीर लिखी है और उसकी तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसने तहरीर को कागज संख्या 4/ए-1 के रूप में साबित किया। अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, उसने अभियोजन पर किसी विवाद का उल्लेख नहीं किया है।

17. पी.डब्ल्यू.-2 चंद्र किरण ने कहा कि वह महेंद्र, बांके, नेमपाल और पप्पू को जानता है। बांके महेंद्र का भाई है, नेमपाल महेंद्र की बुआ का बेटा है और पप्पू उनका दोस्त है। मृतक फतेह सिंह उसका बड़ा भाई था। इस घटना के घटित होने से 2, ढाई महीने पहले, महेंद्र ने एक बाबू की बेटी को अपने घर में रात भर के लिए रखा था जिसके कारण उनके बीच झगड़ा हुआ था। महेंद्र ने उसके भाई को धमकी दी थी। लगभग 10 साल और 2 महीने पहले, उसके पिता शिव चरण, उसका भतीजा राकेश और उसका भाई फतेह सिंह एक नेता का भाषण सुनने गए थे। भाषण सुनने के बाद, वे शाम 5:00 बजे घर के लिए निकले। जब वह अपने भाई के साथ तिराहे पर पहुंचा, तब लक्ष्मण के घर के पास, महेंद्र, पप्पू, बांके और नेमपाल नामक चार व्यक्ति अपने हाथों में पिस्तौल लिए लक्ष्मण के घर से बाहर आए। महेंद्र ने उसके भाई को यह कहते हुए ललकारा कि वह आज बच नहीं सकता और चारों व्यक्तियों ने उसके भाई फतेह सिंह पर गोली चला दी और वे नहर की ओर भाग गए। शोरगुल सुनकर गांव वाले मौके पर आ गए। उसने कहा कि राकेश और उसके पिता शिव राम ने इस घटना को देखा था। घटना उसके घर से लगभग 35-40 गज की दूरी पर हुई थी। अभियुक्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उसने यह नहीं गिना कि कितनी गोलियां चलाई गईं। वे घटना के समय उपस्थित थे। गांव से कोई नहीं आया था। उसने आगे कहा कि उसका भतीजा घटना के लगभग साढ़े 5

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घंटे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गया है। उसे यह नहीं पता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने उसके साथ कौन गया है।

18. पी.डब्ल्यू.-3 सुंदर पाल सिंह, कांस्टेबल ने कहा है कि 24.08.1995 को, वह स्याना पुलिस स्टेशन में तैनात था। उस तिथि को, थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह (पी.डब्ल्यू.-5), उप-निरीक्षक जगदीश सिंह और कांस्टेबल किशन सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। उप-निरीक्षक जगदीश सिंह ने पंचायतनामा तैयार किया और शव को सील कर दिया तथा पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेजने हेतु शव उसे सौंप दिया और उसके बाद शव उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

19. पी.डब्ल्यू.-4, डॉ. एम.के. बंसल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, बुलंदशहर ने 25.08.1995 को शाम लगभग 4.00 बजे मृतक फतेह सिंह का पोस्टमार्टम परीक्षण किया। मृतक की आयु लगभग 40 वर्ष थी और उसकी एक दिन पहले मृत्यु हुई थी। वह औसत शरीर का था, उसके दाहिने कान से खून रिस रहा था। पूरे शरीर में मृत्यु पश्चात कठोरता उपस्थित थी। मृतक के शव पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

(1) सिर के पिछले हिस्से पर 1 सेमी x 1 सेमी x मस्तिष्क की गहराई तक आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव। दाहिने कान से 6 सेमी दूर और ऊपर, कालापन और गुदना उपस्थित।

(2) गर्दन के बाईं ओर 1.5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी की गहराई तक आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव। बाएं कान की लोब्यूल से 4 सेमी दूर और नीचे। कालापन और गुदना उपस्थित।

(3) चेहरे के दाहिनी ओर 1.5 सेमी x 1 सेमी छिला हुआ नील। दाहिनी आंख के 2 सेमी नीचे पार्श्व पहलू पर।

(4) दाहिने सीने पर 3.5 सेमी x 3.00 सेमी x गुहा की गहराई तक आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव। 7 बजे की स्थिति में दाहिने निप्पल से लगभग 20 सेमी नीचे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आंतरिक परीक्षण पर दाहिनी ओर की ओसीसीपिटल हड्डी टूटी हुई थी और झिल्लियां फटी हुई थीं। मस्तिष्क फटा हुआ था और चोट संख्या 1 के पास हेमेटोमा उपस्थित था। प्लूरा फटा हुआ पाया गया। दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था। हृदय खाली था। दाहिनी फुफ्फुस गुहा में एक लीटर रक्त उपस्थित था। पेरिटोनियम फटा हुआ था। उदर गुहा में 2 लीटर रक्त उपस्थित था। आमाशय में 40 ग्राम अर्ध-ठोस खाद्य सामग्री पाई गई। आंते कई स्थानों पर फटी हुई थीं। यकृत भी फटा हुआ था। चोट संख्या 1 से 2 धातु के टुकड़े बरामद हुए, चोट संख्या 2 से एक धातु का टुकड़ा बरामद हुआ, चोट संख्या 4 से 30 छोटे धातु के छर्रे बरामद हुए। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव था।

20. पी.डब्ल्यू.-5 वीरेंद्र सिंह, वाद के विवेचना अधिकारी ने कहा है कि 24.08.1995 को, वह पुलिस स्टेशन स्याना के प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में दर्ज की गई थी। वर्तमान वाद की विवेचना उन्हें सौंपी गई थी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, पंचायतनामा का फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, वह घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पंचायतनामा तैयार करने वाले उप-निरीक्षक जगदीश सिंह के निर्देश पर अपनी उपस्थिति में गवाह का बयान दर्ज किया। उन्होंने इस दस्तावेज को प्रदर्श क-3 से प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया। उन्होंने नक्शा-नजरी तैयार किया और प्रदर्श क-10 को साबित किया। उसके बाद उन्होंने धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

21. पी.डब्ल्यू.-6 हेतराम सिंह, कांस्टेबल ने 24.08.1995 को कहा कि वह उस समय कांस्टेबल क्लर्क था। उसने जीडी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया और प्रदर्श क-13 और क-14 के रूप में साबित किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का प्रश्न है, घटना 24.08.1995 को शाम लगभग 5:00 बजे घटित होना अभिकथित है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 24.08.1995 को रात 10:45 बजे दर्ज की गई थी। लिखित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तों के डर और किसी वाहन की अनुपलब्धता के कारण, सूचनादाता छिपते हुए पुलिस स्टेशन आया। सूचनादाता मृतक का पुत्र है और मामले के चश्मदीद गवाह ने प्रति-परीक्षा में विलंब को स्पष्ट किया है। उसने कहा कि घटना के बाद, घर के सदस्यों को सूचना दी गई और उसके बाद वह लगभग एक घंटे तक शव के पास रहा और जब उसके परिवार के सदस्य घटना स्थल पर आए तब वह शव के पास रोशनी की व्यवस्था करने के बाद पुलिस स्टेशन गया था।

किलाक्कथा परमबाथ ससी और अन्य बनाम केरल राज्य एआईआर 2011 एससी 1064 में यह टिप्पणी किया गया है कि:-

"जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की जाती है, तो यह अनुमान सही रूप से निकाला जा सकता है कि अभियोजन की कहानी सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन समान रूप से दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अभियोजन की कहानी असीम रूप से मजबूत हो जाती है।"

हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में मात्र विलंब को अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं माना जाता है, लेकिन अभियोजन पक्ष के लिए विलंब को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करना बाध्यकारी है और न्यायालय को वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में इसका संज्ञान लेना चाहिए।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद 2001 (6) एससीसी 71 में, जहां सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार व्यक्त किया है: -

"प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का उपयोग अभियोजन के मामले पर संदेह करने और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब के आधार पर इसे खारिज करने के लिए एक कर्मकांडी सूत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। विलंब का प्रभाव न्यायालय को यह खोजने के लिए सतर्क करने का होता है कि क्या विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, और यदि दिया गया है, तो क्या वह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष विलंब को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन के संस्करण में अतिशयोक्ति की संभावना है, तो विलंब अभियोजन के लिए घातक होगा। हालांकि, यदि विलंब को न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्पष्ट कर दिया जाता है, तो विलंब अपने आप में संपूर्ण अभियोजन के मामले पर अविश्वास करने और उसे खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।"

चूंकि पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब के कारण के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, और इसलिए, अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

23. जहां तक अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 हितबद्ध गवाह हैं, यह सच है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 मृतक के संबंधी गवाह हैं। 'संबंधी' 'हितबद्ध' के समतुल्य नहीं है। किसी गवाह को हितबद्ध केवल तभी कहा जा सकता है, जब वे मुकदमेबाजी के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं और किसी अभियुक्त को दंडित होते हुए देखते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि यदि गवाह मृतक के साथ मैत्रीपूर्ण रूप से संबंधित हैं तो उनका साक्ष्य केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अन्य परिस्थितियां इसे विश्वसनीयता के अयोग्य न बना दें। जहां तक पी.डब्ल्यू.-1 के अपनी प्रति-परीक्षा में दिए गए इस बयान का प्रश्न है, कि 'नेताजी का भाषण रात लगभग 8 बजे समाप्त हुआ और वे उसके लगभग एक से डेढ़ घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे', यह ध्यान देने योग्य है कि घटना 24.08.1995 को हुई थी और मुख्य-परीक्षा 01.09.1997 को दर्ज की गई थी, लेकिन अभियुक्त के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रति-परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और अंततः 06.10.2005 को, 10 वर्ष से अधिक समय के बाद उसकी प्रति-परीक्षा आयोजित की गई थी और समय बीतने के साथ, मानवीय स्मृति कमजोर हो जाती है। यह विसंगति जो अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है, कोई दुर्बलता उत्पन्न नहीं करती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, अपनी मुख्य-परीक्षा में और अपनी प्रति-परीक्षा में एक बार, पी.डब्ल्यू.-1 ने विशेष रूप से कहा है कि घटना का समय लगभग शाम 5-5:30 बजे है।

पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा है कि जब मृतक लक्ष्मण के घर के सामने पहुंचा तब अभियुक्तों द्वारा उस पर गोली चलाई गई और जब मृतक ने भागना शुरू किया, तो उसका पीछा किया गया और उसे घेरने के बाद उस पर गोलियों के और राउंड चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप वह फूल सिंह के खेत में जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पी.डब्ल्यू.-1 के बयान में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था।

24. जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में मंतव्य का खुलासा न करने का प्रश्न है, यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विवरणों की सामग्री के रूप में कोई विश्वकोश नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह (2003) 6 एससीसी 175 में; माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी किया गया: (एससीसी पीपी 183-84, प्रस्तर 20 और 22)

"20. यह सुस्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है, जिसे सूचित किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। कोई सूचनादाता किसी अपराध के घटित होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही वह पीड़ित या हमलावर का नाम न जानता हो। उसे यह भी पता नहीं हो सकता है कि घटना कैसे हुई। यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचनादाता कोई चश्मदीद गवाह हो ताकि वह किए गए अपराध के सभी पहलुओं का विस्तार से खुलासा कर सके। महत्वपूर्ण यह है कि दी गई सूचना में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होना चाहिए और इस प्रकार दर्ज की गई सूचना पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने पर संदेह करने का आधार प्रदान करनी चाहिए। इस स्तर पर इतना ही पर्याप्त है कि यदि पुलिस अधिकारी दी गई सूचना के आधार पर संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करता है, और यह नहीं कि उसे आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। यदि प्राप्त सूचना के आधार पर उसे संदेह करने का कारण है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया होगा, तो वह सूचना दर्ज करने और विवेचना करने के लिए बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना भी आवश्यक नहीं है। पूरी विवेचना के बाद ही वह सूचना की सत्यता या अन्यथा पर रिपोर्ट देने में सक्षम हो सकता है। इसी प्रकार, भले ही सूचना सभी विवरण प्रदान नहीं करती है, उसे विवेचना के दौरान उन विवरणों का पता लगाना चाहिए और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने चाहिए। संज्ञेय अपराध के घटित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होने का खुलासा करने वाली दी गई सूचना केवल सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने और उसके बाद विधि के अनुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से विवेचना तंत्र को गतिमान करती है। सही परीक्षण यह है कि क्या प्रदान की गई सूचना अपराध के घटित होने पर संदेह करने का कारण प्रदान करती है, जिसकी विवेचना करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत सशक्त है। यदि ऐसा है, तो उसके पास सूचना दर्ज करने और स्वयं मामले की विवेचना करने या विवेचना करने के लिए किसी अन्य सक्षम अधिकारी को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह प्रश्न कि क्या रिपोर्ट सत्य है, क्या यह घटना के तरीके के बारे में पूरा विवरण प्रकट करती है, क्या अभियुक्त नामजद है, और क्या आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये सभी ऐसे विषय हैं जो इस प्रश्न के विचार से भिन्न हैं कि क्या रिपोर्ट संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है। भले ही सूचना इन मामलों के संबंध में पूरा विवरण नहीं देती है, विवेचना अधिकारी मामले की विवेचना करने और सत्य तथ्यों को खोजने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होता है, यदि वह ऐसा कर सकता है।"

इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल रूप से विवेचना तंत्र को गतिमान करने का एक तंत्र है और यह अपराध का विस्तृत विश्वकोश होने के लिए अभिप्रेत नहीं है। विधिक रूप से, सूचनादाता को पल-पल का विवरण प्रदान करने या शामिल सभी पक्षों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि, दस्तावेज पर्याप्त है यदि यह एक संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करता है, जो पुलिस को कार्य करने के लिए संदेह करने का कारण प्रदान करता है।

25. जहां तक समय-पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय-पूर्व दर्ज की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पी.डब्ल्यू.-6, कांस्टेबल हेतु राम सिंह ने रात 22.45 बजे की जीडी प्रविष्टि संख्या 40 को प्रदर्शक-14 के रूप में साबित किया है और उसके बयान तथा पंचायतनामा रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं है, जो रात 23:15 बजे तैयार की गई थी। अपराध संख्या और धाराओं के विवरण का भी उल्लेख किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचायतनामा रिपोर्ट और पंचायतनामा रिपोर्ट से जुड़े अन्य दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय-पूर्व बनाई गई थी।

26. वर्तमान वाद में, जैसा कि यह स्पष्ट है कि अभियोजन का मामला दो चश्मदीद गवाहों के आंखों देखे हाल पर आधारित है और उनकी गवाही में कोई बड़ी दुर्बलता या विसंगति नहीं बताई जा सकी है। उपर्युक्त सभी कारक मामूली विसंगतियां हैं और पी.डब्ल्यू.-1 तथा पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही के सार को प्रभावित नहीं करती हैं। जहां तक उपर्युक्त विसंगतियों का संबंध है, सभी आपराधिक मामलों में, गवाहों के बयानों में अवलोकन की सामान्य त्रुटि के कारण सामान्य विसंगतियां होना तय है, अर्थात् समय बीतने के कारण स्मृति की त्रुटियां या मानसिक स्थिति, जैसे कि घटना के समय सदमा और भय। जहां चूक एक विरोधाभास के रूप में है जो गवाहों की सत्यता के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा करती है और अन्य गवाह भी न्यायालय में गवाही देते समय तात्त्विक सुधार करते हैं, ऐसे साक्ष्य पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालांकि, मामूली विरोधाभास, विसंगतियां, विस्तार या तुच्छ मामलों में सुधार जो अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिस पर साक्ष्य को संपूर्णता में खारिज किया जा सके। न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी होती है और यह निष्कर्ष दर्ज करना होता है कि क्या उसका बयान विश्वास जगाता है। अतिशयोक्तियां अपने आप में साक्ष्य को कमजोर नहीं बनाती हैं। लेकिन अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए यह उन कारकों में से एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हो सकता है, जब संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए रखा जाता है। इसलिए, किसी गवाह के बयानों में मात्र सीमांत भिन्नताओं को सुधार करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे पहले गवाह द्वारा दिए गए बयान का विस्तार हो सकते हैं। ऐसी चूकें जो तात्त्विक विवरणों में विरोधाभास के समान हैं, अर्थात् जो मामले की जड़ तक जाती हैं / विचारण या अभियोजन मामले के मूल को तात्त्विक रूप से प्रभावित करती हैं, गवाह की गवाही को अमान्य किए जाने योग्य बनाती हैं। [स्टेट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनाम सरवनन एवं अन्य, एआईआर 2009 एससी 152; अरुमुगम बनाम राज्य, एआईआर 2009 एससी 331; महेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 11 एससीसी 334; और डॉ. सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, जेटी 2010 (12) एससी 287]।

27. वर्तमान वाद में, पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों में कोई बड़ा विरोधाभास या विसंगति नहीं बताई जा सकी है। जैसा कि पहले कहा गया है, तुच्छ मामलों में मामूली विरोधाभास, विसंगतियां, अतिशयोक्ति या सुधार जो अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिस पर चश्मदीद गवाही को संपूर्णता में खारिज किया जा सके। न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी होती है और यह निष्कर्ष दर्ज करना होता है कि क्या उसका बयान विश्वास जगाता है। न्यायालय को संपूर्ण तथ्यात्मक परिदृश्य का परीक्षण करने के बाद यह निर्धारित करना होता है कि क्या किसी व्यक्ति ने अपराध में भाग लिया है या उसे झूठा फंसाया गया है। तथ्यों से पूरी तरह परिचित सूचनादाता या गवाह में संपूर्ण घटना के विवरण को बिना कुछ भूले प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कौशल या क्षमता की कमी हो सकती है। कुछ लोग वर्णन में सबसे महत्वपूर्ण विवरण भी भूल सकते हैं। उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था और ऐसे कोई कारण नहीं दिखाए जा सके कि ये गवाह अपीलकर्ताओं के विरुद्ध झूठी गवाही क्यों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



देंगे। वर्तमान वाद का परीक्षण परिस्थितियों की समग्रता में और पूर्वोक्त विधिक प्रस्तावों के प्रकाश में की जानी आवश्यक है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और अभिलेख पर तथ्यों तथा साक्ष्यों के पूर्वोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत, हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियोजन पक्ष सभी अपीलकर्ताओं के अपराध को सिद्ध करने में सफल रहा है।

28. हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं महेंद्र, बांके और पप्पू उर्फ महिपाल को उचित रूप से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है। इसलिए, विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वे पुष्ट किए जाने योग्य हैं।

29. तदनुसार, आपराधिक अपीलें खारिज की जाती हैं।

30. सभी तीनों अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभूति बंधपत्र रद्द किए जाते हैं। उन्हें तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए और दण्ड के शेष भाग को काटने के लिए कारागार भेजा जाए।

31. अनुपालन के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

32. विचारण न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

33. विद्वान न्याय मित्र श्री सचिन कनौजिया ने इस न्यायालय की कुशलतापूर्वक सहायता किया है और उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण से उन्हें उनके पारिश्रमिक के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान किया जाए।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18 मार्च, 2026

एस.के.एस.

Translated Versionn. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”